एक वैध लक्ष्य के लिए अनुचित प्रयास

द हिन्दू

" आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमे निजी निवेश में वृधि के लिए कहीं गयी बात सही है,

लेकिन यह पुरवि ऐसिआ माडल से अपने आप को अलग कर रही है।"

हाल ही में जारी आर्थिक सवैक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था दवारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियौ की या तो अनदेखी करता है या इस इन चुनौतियौ का बोध नहीं है। इन चुनौतियौ में गंभीर कृषि संकट; घाटे में चल रही और कर्ज में डूबी सार्वजनिक छेत्र की इकाईया; और सार्वजनिक छेत्र के बैंको को परेशान करने वाले मुद्दे शामिल है।

हालाकि, सवेक्षण मनोविज्ञान से अर्थशास्त्र में अन्तद्रइस्ति को शामिल करने के महत्व को उजागर करने में गलत नहीं है , लकिन यह अजीब है कि इसे इतनी देर से किया गया । यू. के., ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे कई अन्य देशो दवारा भी लंबे समय से निति िडजाइन क्षेत्रौ में इस तरह के बिंदुओं को लागू किया जा रहा है और इस मुद्दे पर पिछले कुछ वर्षो में भारत में चर्चा हुई है ।

एक मुद्दे को सवेक्षण ने सही रूप से रेखांकित किया है कि भारत को निजी निवेस को पुनजीॅिवत करने की आवश्यकता है, यदि इसे २०२४-२५ तक जादुई ५- टीलीयन डालर वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करना है । हालाकि, यहाँ जो अजीब है, वह यह है की इस पर जोर देने के लिए दस्तावेज भारत पूर्वी एशिया देशो के बीच सदियों पुरानी तुलना को आमंत्रित करता है।

कैसे एनआईई सम्रध हुआ ?

यहाँ, एक सवाल जो उठता है वह यह है की क्या पूर्वी एशिया माडल भारत की

उलझी हुई निवेश दरो को पुनजिवित करने में मद्द कर सकता है? कुछ महत्व अनुस्मारक रेखांकित करने योग्य हैं ।

पूर्वी एशिया माडल काफी हद तक सिंगापुर,होंगकोंग, दक्षिण कोरिया और ताइवान तथा जापान के नव ओधौगीक्त अर्थव्यवस्था दवारा संचालित एक कहानी थी ।

विशेष रूप से, 1960 के दशक से 1990 के दशक तक विभिन्न एनआईई में मुख्य लक्ष्य सकल बचत दरो को बढ़ाना था । जबकि घरेलू बचत में विरधि आसाकिक रूप से सकारात्मक जनस्याखकीय लाभाश के कारण हुई, कई अन्य कारको, जिनमे व्यापक आर्थिक सिथिरता सामाजिक सुरक्षा की कमी, लाभ उठाने में असमर्थता और बाध्यकारी बचत शामिल है, ने भी एक भूमिका निभाई है । राज्य के स्वामित्व वाले घमो को बजट की कमी के साथ काम करना पड़ता था ।

एक अन्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था की निजी बचत को वास्तव में औप्चारिक वितीय प्रडाली में मध्यवर्ती किया जाना था, जिसमे यह विफल रहा क्योकि पूजी की लागत अधिक रही और निवेश के लिए पूजी की उपलब्धता कम रही । इसे प्राप्त करने के लिए, एक सुरछित सार्वजानिक छेत्र की बैंकिग

प्रणाली की स्थापना को महत्व दिया गया था, जहा केंद्रीय बैंक दवारा जमा की गारंटी दी गई और ब्याज आय पर हल्के से कर अधिरोपित किया गया था । राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को बेहतर दंग से विनीमियत किया गया था क्योकि वितीय इस्थिरता संग्रम व्यापक आर्थिक इस्थिरता की आधारशिला थी । वितीय समावेशन को प्रोत्साहित किया गया था । हालाकि ध्यान केवल उनके खातो को खोलने के वास्तविक्ता उपयोग पर था । जबकि निर्माण छेत्र को एक विकास इंजन के रूप में देखा गया था और निर्यात प्रतिसपर्धा के लिए खुला था, बैंकिंग छेत्र, होंगकोंग के अलावा सभी अर्थव्यवस्थाऔ में, बेहतर विनियमित और विदेशी बैंको के लिए बंद था । यहाँ तक की सिंगापुर ने शुरु में एक दोहरी बैंकिंग सरचना को अपनाया, जिसमे घरेलू अर्थव्यवस्था को बड़े पएमाने पर महत्वपूड अल्पकालिक बैंक प्रवाह से आश्रय दीया । 1990 के दशक के अंत तक पूरी तरह से लाइसेंसे प्राप्त विदेशी बैंको को अनुमति देने के लिए इसने एक आशंकित नीति का शहरा लिया ।

तंग वितीय निरीक्षण

यह सामान्य परिस्तितियो में, ओंप्चरिकता वितीय प्रडाली से विघटन का कारण होगा, जिसके रिजल्ट की मात्रा में कमी और शैडो प्रडाली का निर्माण होगा । हालाकि, इन अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने कड़ी निगरानी बनाये रखी और चयनात्मक पूजी ने यह सुनिश्चित किया कि कम उपज वाली बचत ने अपने मूल देशो को नहीं छोड़ा, जबकि सीमित वितीय विकास ने बचत के विकल्प की तलाश कर रहे लोगो की संभवाना को कम कर दिया ।

इनके साथ ही, सरकारो ने घरेलू निवेश को बढावा देने के लिए परिष्कृत ओधोगिकी नितिया अपनाई, जिनमे से अधिकांश निर्यात-नेतित्वा वाली थी ।

सरकार समझती थी कि एक ओधोगिक नीति एक छतीज ओधोगिक नीति के

बिना काम नहीं करेगी ।

विषम नीतिया, सुधार

इस प्रकार, पूर्वी एशिया देशो में निवेस और निर्यात की अदिकता विस्मतावादी नीतियों और सुधारों के कारड थी, जिसे सावधानीपूर्वक जाचा गया था, अच्छी तरह से अनुक्रित किया गया था । इन उपायों ने राष्ट्र को अपने जन्संखियो लाभंस से रिकॉर्ड समय में खुद को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने की अनुमति दी ।

इसके विपरीत, राजनितिक और अन्य मजबूरियों के कारड,1991 के बाद से भारत के सुधारो में बहुत जल्दबाजी हुई है और विकृत रिजल्ट के साथ एक 'स्टाम्प-एंड-ग्रो' प्रकृति बनी हुई ।

आर्थिक समीक्षा 2018-19

. हाल ही में केंद्रीय वित् और कॉर्पोरेट मामलो की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन में ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश की ।

. बेटी बचाओ बेटी पढाओ से बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी किया गया ।

. सुन्दर भारत किया गया ।

. एलपीजी सब्सिडी के लिए 'गिव इट अप' 'थिंक अबाउट द सब्सिडी' किया गया ।

. कर वंचना से कर अनुपालन किया गया ।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

. 2018-19 में भारत अब तेजी से बढती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है ।

. जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 7.2 प्रतिशत की जगह वर्ष 2018-19 में 6.8 प्रतिशत हुई ।

. 2018-19 में विकास दर में तेजी आएगी और इसके 7% रहने का अनुमान है।

. 2018-19 में मुद्रफिस्ती की दर 3.4 प्रतिशत तक सीमित रही ।

. चालू खाता घाटा जीडीपी के 2.1 प्रतिशत पर समायोजित करने योग्य है ।

राजकोसिय घटनाक्रम

. जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे और 44.5 प्रतिशत के ऋड-जीडीपी अनुपात के साथ वित् वर्ष 2018-19 का समापन ।

. छोटी फर्मो का रोजगार में केवल 14 प्रतिशत और उतापदाकता में 8% योगदान है ।

आर्थिक समृधि के लिए लक्ष्य

. क़ानूनी सुधारो पर जोर देना होगा ।

. नीति समंजस्य सुनिश्चित करना ।

. डाटा को सार्वजनिक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना ।

. पूजी लागत घटाना ।

. निवेश के लिए व्यापार में लाभ जोकिम को तर्कसंगत बनाना ।

मूल्य और महगाई दर

. सीपीआईसी पर आधारित महगाई दर में लगातार 5 वे वर्ष गिरावट दर्ज की गई । पिछले 2 वर्षो से यह 4 प्रतिशत से कम रही है ।

. 2018-19 के दवरान सीपीआई-सी आधारित मंहगाई दर के मुख्य कारक है- आवास, ईधन व अन्य ।

उधोग और अवसरचना

. 2018-19 में 8 बुनियादी उद्योग के कुल सूचकांक में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि

. बिजली की इस्थपित छमता 2019 में 3,56,100 मेगावाट रही, जबकि 2018 में यह 3,44002 मेगावाट थी ।

संभावित प्रश्न(प्रारंभिक परिछा)

१. आर्थिक समीक्षा 2018-19 के संदभ में नींमनलिखित कथनों पर विचार करे-

१. 2018-19 तक देश की जीडीपी की विर्धी दर 6.8 प्रतिशत रही ।

२. 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को पाच ट्रिलियन डॉलर की अर्थवयवस्था बनाने के लिए 8% की सतत वास्तविक जीडीपी विकास दर की जरुरत है ।

३. 2018-19 में मुद्रसिफिती की दर 3.4 % तक सिमित रही।

उपयुँक्त में से कोन- से कथन सत्य है ?

a. 1 और 2 b. 2 और 3

c. 1 और 3 d. उपयुक्त सभी

संभावित प्रश्न(मुख्य परिछा) (250 शब्द)

नव ओदोगिकृत अर्थव्यवस्था के विषय में पूर्वी ऐशिया माडल की चर्चा करे ।